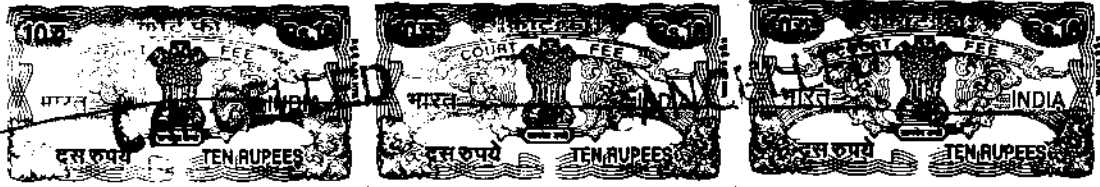


24
249

न्यायालय में राजस्व मण्डल क्वालियर (म.प्र.) कैम्प रीवा,



अब्दुल मोमिन खान आत्मज हलीम खान निवासी ग्राम मेढकी हाल निवास सोहागपुर,
वार्ड नं० 1 शहडोल तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म०प्र०) — निगराकार

R-4102-II/12

बनाम

1. शब्बीर अहमद पिता स्व० तैयब खान,
2. जिबरील खान पिता स्व० हनीफ खॉन
दोनों निवासी ग्राम मेढकी, तहसील पाली, जिला उमरिया (म.प्र.)
3. म०प्र०शासन — गैरनिगराकार

3561

श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय, उमरिया म०प्र०
के प्र०क्र० 55/पुन०/2010-11 में पारित
आदेश दिनांक 16.10.12 के विरुद्ध पुनरीक्षण
अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०मू०रा०सं० 1959

47212

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर रहा है :-

निगरानी के तथ्य

1. यह कि आराजी क्र० 151 रकवा 1.124 हे०, स्थित ग्राम मेढकी, प०ह० सलैया, सर्किल अमिलिहा, तहसील पाली, जिला उमरिया (म०प्र०) निगराकार के भूमि स्वामी स्वत्व व अधिपत्य की भूमि है, माह जनवरी-फरवरी 2007 में जिबरील खान आत्मज स्व० हनीफ खान निवासी ग्राम मेढकी के द्वारा उपरोक्त भूमि के अंशभाग 0.020 हे० पर जबरदस्ती खाई खोदना शुरू किया निगराकार के मना करने पर उसने व्यक्त किया कि वह शब्बीर अहमद आत्मज तैयब खान निवासी ग्राम मेढकी की भूमि पर खाई खोद रहा है।
2. यह कि जिबरील खान के द्वारा सीमा का विवाद प्रारंभ करने पर निगराकार न्यायालय तहसीलदार महो०पाली जिला उमरिया के समक्ष सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो रा०प्र०क्र० 10-अ-12/06-07 में पंजीकृत किया जाकर रा०नि०क्र० अमिलिहा को सीमांकन हेतु आदेशित किया था। वक्त सीमांकन यह प्रमाणित हुआ था कि जिबरील खान निगराकार के भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि पर खाई खोद रहा है।
3. यह कि रा०नि०म० अमिलिहा के द्वारा किये गये सीमांकन को गैर निगराकारगणों के द्वारा तहसीलदार पाली के समक्ष आक्षिप्त नहीं किया गया फलस्वरूप तहसीलदार पाली के द्वारा दिनांक 09.04.07 को सीमांकन का कनफरमेशन कर दिया गया। जिसे

(Handwritten signature)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R4102-IV/12

जिला-उमरिया

अब्दुल मोमिन खान/ शब्बीर अहमद

(1)	(2)	(3)
<p>3-8-19</p>	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 55/पुनर्वालोकन/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	

M